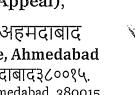


आयुक्त(अपील)का कार्यालय,

Office of the Commissioner (Appeal),





केंद्रीय जीएसटी, अपील आयुक्तालय,अहमदाबाद Central GST, Appeal Commissionerate, Ahmedabad जीएसटी भवन, राजस्वमार्ग, अम्बावाड़ीअहमदाबाद३८००१५. CGST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015 **2** 07926305065 टेलेफैक्स07926305136

DIN: 20221264SW00000D09D

स्पीड पोस्ट

फाइल संख्या : File No : GAPPL/COM/STD/150/2022 159 39 - 113 क

अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal No. AHM-EXCUS-001-APP-094/2022-23 रव दिनाँक Date : **12-12-2022** जारी करने की तारीख Date of Issue 14.12.2022

आयुक्त (अपील) द्वारापारित Passed by Shri Akhilesh Kumar, Commissioner (Appeals)

- Arising out of OIO No. WS07/O&A/OIO-131/AC-RAG/2021-22 दिनाँक: 09.03.2022 passed by ग Assistant Commissioner, CGST, Division VII, Ahmedabad South
- अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address

Appellant

1. The Assistant Commissioner CGST, Division VII, Ahmedabad South 3rd Floor, APM Mall, Nr. Seema Hall, Anandnagar Road, Satellite, Ahmedabad

Respondent

M/s Accutron Inc. India 402-403, Shapath-II, S.G. Highway, Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पूनरीक्षण आवेदन प्रस्तूत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन

Revision application to Government of India:

- केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।
- A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:
- यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to ar factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a use or in storage whether in a factory or in a warehouse.

- (क) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।
- (A) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (ख) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।
- (B) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (c) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए—8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल—आदेश एवं अपील आदेश की दो—दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ.का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35—इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर—6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/-फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- कीं फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35—बी/35—इ के अंतर्गत:—

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तितिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण(सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2nd माला, बहुमाली भवन , असरवा , गिरधरनागर, अहमदाबाद—380004

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होत हुए भी कि लिखा पढी. कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्कअधिनियम 1970 यथासंशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू.6.50 पैसे कान्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(65) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण(सिस्टेट), के प्रतिअपीलों के मामले में कर्तव्यमांग(Demand) एवं दंड(Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded)-

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि:
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि:
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.
- ⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया
 है.

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

.(cxcvi) amount determined under Section 11 D;

(cxcvii)

amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(cxcviii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where ty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-VII, Commissionerate- Ahmedabad South (hereinafter referred to as the appellant), on the basis of Review Order No. 12/2022-23 dated 06.06.2022 passed by the Principal Commissioner, Central GST, Ahmedabad South Commissionerate in terms of Section 84 (1) of the Finance Act, 1994, against Order in Original No. WS07/O&A/OIO-131/AC-RAG/2021-22 dated 09.03.2022 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Assistant Commissioner, CGST, Division-VII, Commissionerate- Ahmedabad South [hereinafter referred to as "adjudicating authority"] in the case of M/s. Accutron Inc. India, 402-403, Shapath-II, S.G. Highway, Ahmedabad [hereinafter referred to as the respondent].

- 2. Briefly stated, the facts of the case is that as per the information received from the Income Tax Department, the respondent had earned substantial income from services amounting to Rs.1,78,83,000/- during F.Y. 2014-15, however, the respondent did not obtain service tax registration and did not pay service tax on the service income. The respondent was requested vide letters on different dates to submit the documentary evidence in respect of their income. However, the respondent failed to submit the required details/documents and neither was any explanation/clarification submitted regarding the income earned. Therefore, the service income earned by the respondent was considered as taxable value and it appeared that the respondent had failed to pay the service tax amounting to Rs.22,10,339/-. Therefore, the respondent was issued Show Cause Notice bearing No. V/WSO7/O&A/SCN-77/AAHCA7108F/2020-21 dated 23.09.2020 wherein it was proposed to:
 - A. Demand and recover the service tax amounting to Rs.22,10,339/under the proviso to Section 73 (1) of the Finance Act, 1994 along with interest under Section 75 of the Finance Act, 1994.
 - B. Impose penalty under Sections 77(1) and 78 of the Finance Act, 1994.



- C. Recover late fee in terms of Rule 7C of the Service Tax Rules, 1994 read with Section 70 of the Finance Act, 1994.
- 2. The SCN was adjudicated vide the impugned order and the proceedings initiated against the respondent were vacated.
- 3. Being aggrieved with the impugned order, the appellant department have filed the present appeal on the following grounds:
 - i. The adjudicating authority has erred in dropping the demand of service tax without recording any finding on the merits of the case and the impugned order is a non-speaking order.
- ii. The adjudicating authority has recorded finding that the respondent had receipts in USD and the converted amount in Rupees matched with the figures shown in the SCN.
- iii. The adjudicating authority has reproduced the submission of the respondent that they were acting as a branch office of the company having head office in USA and that they had provided certain services to the head office for which they are receiving fund towards reimbursement of expenditure incurred by them. Based on this, the adjudicating authority has concluded that as the service recipient is located outside the taxable territory, service tax cannot be demanded.
- iv. However, he has not given any finding as to how the amount received by the respondent is not subject to service tax. No findings have also been given on the submissions made by the respondent.
- v. The adjudicating authority has not given any findings as to whether the income of the respondent is reimbursement of expenditure or job work income or it is export of service and hot the same is not subject to service tax.
- 4. Personal Hearing in the case was held on 07.12.2022. Shri Anil K. Parekh, Chartered Accountant, appeared on behalf of the respondent for the hearing. He stated that they had earned income by way of job work to parent company and the amount has been in nature of re-imbursement, which is

exempt. He stated that he would make a written submission as crossobjection.

6

- 5. In the written submission filed on 07.12.2022, the respondent, contended, inter alia, that:
 - > As per Rule 5 of the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006, reimbursement of expenditure as a pure agent is exempted from service tax.
 - > They are acting as a Branch office of Accutron Inc. USA which is situated outside India. They are providing certain services to the Head Office for which the head office is remitting funds towards reimbursement of expenditure incurred by them. They are acting as a Pure Agent and for Income Tax purposes, they follow 'cost plus method or markup pricing strategy' for transfer pricing and pay income tax accordingly.
 - ➤ The amount of Rs.1,78,83,000/- is actually amount received from head office as reimbursement of expenditure, which is shown as job work in their books of accounts. Accordingly, the same is exempted from service tax and they do not require any service tax registration.
 - > Their job work income is exempted service tax and they are not also not liable for interest or penalty.
 - ➤ They submit copies of the ITR for F.Y. 2014-15, Form 26AS, Audited Financial Statements for F.Y. 2014-15, Copy of Transfer Pricing Audit Report in Form 3CEB and copy of Bank Statement.
- 6. I have gone through the facts of the case, submissions made in the Appeal Memorandum, the written submissions filed by the respondent and the material available on records. The issue before me for decision is whether the impugned order dropping the demand of service tax amounting to Rs.22,10,339/-, in the facts and circumstances of the case, is legal and proper. The demand pertains to F.Y. 2014-15.



- 7. The appellant department has contended that the adjudicating authority has merely reproduced the submissions of the respondent and not given any findings on the same. It is observed that the respondent have contended that they are acting as pure agent of the head office situated outside India and that the funds remitted by the head office is towards reimbursement of expenditure incurred by them. At the same time, the respondent are also claiming that they are doing job work for the head office and the same is exempted from service tax.
- 8. It is observed from the Profit and Loss Account submitted by the respondent that for F.Y. 2014-15, they have reported an amount of Rs.1,78,83,000/- under 'Revenue from Operations'. In Note 12 to the P&L Account, the same is reported to be job work income. Further, in Form 3CEB under Part B, it is stated that "Manufacture of PCB's Material Procurement Planning Services Provided by the Branch". From the documents submitted by the respondent, it appears that they are providing services to their parent company located outside India. However, the documents do not indicate that the respondents are engaged in job work on behalf of the parent company. At the same time, the documents submitted by the respondent also indicate that the amounts received by them from the parent company are not towards reimbursement of expenditure, as claimed by them.
- 8.1 The documents submitted by the respondent do not indicate the actual nature of the service provided by them to their head office and whether the same falls within the purview of export of service. Therefore, I am left with no option but to remand it back to the adjudicating authority to decide the matter afresh after examining the relevant documents and give a clear finding on the nature of services provided by the respondent and whether the same are within the ambit of export of services. The respondent are also directed to submit all the relevant documents before the adjudicating authority within 15 days from the date of receipt of this order. The adjudicating authority shall follow the principles of natural justice before the specific passing an order in the remand proceedings.

8

- 9. In view of the facts discussed hereinabove, I set aside the impugned order and the appeal filed by the appellant department is allowed by way of remand.
- 10. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

 The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

(Akhilesh Kumar) Commissioner (Appeals)

Date: 1

Attested:

(N.Suryanarayanan. Iyer) Superintendent(Appeals), CGST, Ahmedabad.

BY RPAD / SPEED POST

To

The Assistant Commissioner,

CGST, Division-VII,

Commissionerate: Ahmedabad South.

M/s. Accutron Inc. India, 402-403, Shapath-II, S.G. Highway, Ahmedabad Appellant

Respondent

Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone.
- 2. The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South.
- 3. The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad South. (for uploading the OIA)

4. Guard File.

5. P.A. File.